राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

एस.बी. आपराधिक विविध (पे.) संख्या 4421/2024

तमन्ना पुत्री दुलीचंद, उम्र लगभग 46 वर्ष, निवासी शास्त्री कॉलोनी, डूंगरपुर, जिला डूंगरपुर (राज.)

----अपीलार्थी

बनाम

राजस्थान राज्य, पी.पी. के माध्यम से

----प्रतिवादी

अपीलार्थी(गण) के लिए : श्री एस.के.वर्मा

प्रतिवादी(गण) के लिए : श्री विक्रम सिंह, पीपी

माननीय श्री न्यायमूर्ति अरुण मोंगा

आदेश

11/07/2024

1. याचिकाकर्ता की शिकायत विद्वान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, डूंगरपुर द्वारा पारित दिनांक 04.04.2024 के आदेश के विरुद्ध है, जिसमें विद्वान ट्रायल कोर्ट द्वारा पारित दिनांक 30.05.2022 और 01.07.2022 के आदेशों को बरकरार रखा गया है, जिसके तहत धारा 216 सीआरपीसी के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए याचिकाकर्ता आरोपी के खिलाफ पहले तय किए गए आरोपों को बदल दिया गया / जोड़ा गया, और आईपीसी की धारा 467, 468, 471 के तहत अतिरिक्त आरोप तय किए गए हैं।

2. संक्षेप में, तत्काल याचिका दायर करने के लिए अग्रणी तथ्य, जैसा कि याचिका में दलील दी गई है, इस प्रकार हैं:

2.1 परिवादी दिलीप शाह ने याचिकाकर्ता के खिलाफ धारा 156(3) सीआरपीसी के तहत एसीजेएम, डूंगरपुर के समक्ष शिकायत दर्ज कराई, जिसमें आरोप लगाया गया कि याचिकाकर्ता डूंगरपुर में चेतना जनजाति छात्रावास के नाम से समाज कल्याण विभाग द्वारा सहायता प्राप्त अनुसूचित जनजाति के लिए बालिका छात्रावास चलाता है और याचिकाकर्ता उक्त छात्रावास का प्रबंधक/प्रशासनिक अधिकारी है। आरोप है

कि याचिकाकर्ता ने फर्जी दस्तावेज तैयार कर छात्रावास में 25 छात्राएं दर्शाई हैं, जबकि वास्तव में वहां केवल 9-10 छात्राएं ही अध्ययनरत हैं और उन्हें समाज कल्याण विभाग आदि से अनुदान मिलता है। परिणामस्वरूप, उनके खिलाफ आईपीसी की धारा 420, 467, 468, 471, 409 और 120बी के तहत अपराध कायम किया गया।

2.2 उक्त शिकायत पुलिस थाना कोतवाली डूंगरपुर, जिला डूंगरपुर को भेजी गई, जिसके परिणामस्वरूप याचिकाकर्ता के खिलाफ धारा 420 आईपीसी के तहत अपराध के लिए एफआईआर संख्या 317/2023 दर्ज की गई और जांच शुरू की गई। जांच के समापन पर, याचिकाकर्ता के खिलाफ धारा 420 आईपीसी के तहत अपराध के लिए आरोप पत्र दायर किया गया।

2.3 मुकदमे के लंबित रहने के दौरान, विद्वान लोक अभियोजक ने धारा 216 सीआरपीसी के तहत विद्वान ट्रायल कोर्ट के समक्ष एक आवेदन प्रस्तुत किया, जिसमें आरोपों को धारा 420 आईपीसी से धारा 420, 467, 468 और 471 आईपीसी में बदलने की मांग की गई। उक्त आवेदन को विद्वान ट्रायल कोर्ट ने 30.05.2022 के आपत्तिजनक आदेश के तहत अनुमति दी। परिणामस्वरूप, याचिकाकर्ता के खिलाफ धारा 420, 467, 468 और 471 आईपीसी के तहत कथित अपराधों के लिए दिनांक 01.07.2022 के आपत्तिजनक आदेश के तहत आरोप तय किए गए।

2.4 दिनांक 30.05.2022 और 01.07.2022 के आक्षेपित आदेश से व्यथित होकर, याचिकाकर्ता ने विद्वान पुनरीक्षण न्यायालय के समक्ष पुनरीक्षण दायर करके इसे चुनौती दी, जिसे भी दिनांक 04.04.2024 के आक्षेपित आदेश द्वारा खारिज कर दिया गया, जिसके तहत विद्वान पुनरीक्षण न्यायालय ने विद्वान ट्रायल कोर्ट द्वारा पारित दिनांक 30.05.2022 और 01.07.2022 के आदेशों को बरकरार रखा। इसलिए, वर्तमान याचिका।

3. उपर्युक्त पृष्ठभूमि में, मैंने याचिकाकर्ता के विद्वान वकील और विद्वान पीपी को सुना है।

4. याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने याचिका में लिए गए आधारों के समान ही अपने तर्क प्रस्तुत किए हैं, जो अन्य बातों के साथ-साथ इस प्रकार हैं:

4.1 निचली अदालतों ने मामले के प्रासंगिक पहलू पर विचार नहीं किया है कि गहन जांच के बाद, याचिकाकर्ता के खिलाफ धारा 420 आईपीसी के तहत अपराध के लिए आरोप पत्र दायर किया गया है। विद्वान ट्रायल कोर्ट ने खुद ही उक्त अपराध के लिए आरोप तय किए हैं। लेकिन अब, अभियोजक द्वारा दायर एक आवेदन के

कारण, याचिकाकर्ता के खिलाफ आरोपों को बदल दिया गया है और उस पर धारा 467, 468 और 471 आईपीसी के तहत अतिरिक्त अपराधों के लिए आरोप लगाए गए हैं जो जांच से याचिकाकर्ता के खिलाफ प्रथम दृष्टया नहीं बनते हैं।

4.2 निम्न न्यायालय इस तथ्य को समझने में पूरी तरह विफल रहे हैं कि सरकारी वकील द्वारा दायर आवेदन पर आरोप में परिवर्तन किया गया है, जबकि यह स्थापित कानून है कि धारा 216 सीआरपीसी को लागू करने की शक्ति न्यायालय के पास निर्णय सुनाए जाने से पहले किसी भी समय किसी भी आरोप में परिवर्तन या जोड़ने के उद्देश्य से सक्षम प्रावधान के रूप में विशेष रूप से सीमित है। किसी भी पक्षकार, न तो शिकायतकर्ता और न ही अभियुक्त या अभियोजन पक्ष को आरोप में कोई वृद्धि या परिवर्तन करने का कोई निहित अधिकार नहीं है। यदि पक्षों द्वारा ऐसा करने की अनुमति दी जाती है, तो आपराधिक न्यायालय के लिए अपनी कार्यवाही समाप्त करना असंभव नहीं होगा और त्वरित सुनवाई की अवधारणा खतरे में पड़ जाएगी।

4.3 इसके अलावा यह प्रस्तुत किया गया है कि मामला वर्ष 2013 से संबंधित है। हालांकि, आरोप में परिवर्तन के लिए आवेदन वर्ष 2022 में यानी लगभग 9 वर्षों की देरी के बाद दायर किया गया था। यदि इस स्तर पर आरोप में परिवर्तन की अनुमति दी जाती है, तो मुकदमे में और देरी होगी, जो याचिकाकर्ता के अधिकारों को नुकसान पहुंचाएगा। हालांकि, नीचे के विद्वान न्यायालय मामले के इस महत्वपूर्ण पहलू की सराहना करने में पूरी तरह विफल रहे हैं। इस प्रकार, आक्षेपित आदेश संधारणीय नहीं हैं और उन्हें रद्द और अपास्त किया जाना चाहिए।

5. इसके विपरीत, विद्वान पीपी का तर्क होगा कि मुकदमे में कोई भी पक्ष न्यायालय की शक्तियों का आह्वान करने और पहले से तय आरोपों में परिवर्तन / परिवर्धन की मांग करने के लिए धारा 216 के तहत आवेदन दायर कर सकता है।

6. केस फाइल का अवलोकन करने और प्रतिद्वंद्वी तर्कों को सुनने के बाद, मैं विद्वान पीपी द्वारा लिए गए रुख से खुद को सहमत नहीं कर पा रहा हूं। सीआरपीसी की धारा 216 की स्पष्ट भाषा अन्यथा सुझाव देती है। त्वरित संदर्भ के लिए, उक्त अनुभाग नीचे पुन: प्रस्तुत किया गया है: -

> "216. न्यायालय आरोप में परिवर्तन कर सकता है।-(1) कोई भी न्यायालय निर्णय सुनाए जाने से पहले किसी भी समय किसी भी आरोप में परिवर्तन या वृद्धि कर सकता है।
>
> (2) प्रत्येक ऐसे परिवर्तन या वृद्धि को अभियुक्त को पढ़कर सुनाया जाएगा और समझाया जाएगा।

(3) यदि आरोप में परिवर्तन या वृद्धि ऐसी है कि न्यायालय की राय में, मुकदमे के तुरंत आगे बढ़ने से अभियुक्त को उसके बचाव में या अभियोक्ता को मामले के संचालन में प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना नहीं है, तो न्यायालय अपने विवेकानुसार, ऐसे परिवर्तन या वृद्धि के पश्चात, मुकदमे को इस प्रकार आगे बढ़ा सकता है मानो परिवर्तित या वृद्धि किया गया आरोप मूल आरोप था।

(4) यदि परिवर्तन या वृद्धि ऐसी है कि मुकदमे के तुरंत आगे बढ़ने से, न्यायालय की राय में, अभियुक्त या अभियोक्ता को पूर्वोक्त रूप से प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है, तो न्यायालय या तो नए मुकदमे का निर्देश दे सकता है या मुकदमे को ऐसी अवधि के लिए स्थगित कर सकता है, जितनी आवश्यक हो।

(5) यदि परिवर्तित या जोड़े गए आरोप में वर्णित अपराध ऐसा है जिसके अभियोजन के लिए पूर्व मंजूरी आवश्यक है, तो मामले को तब तक आगे नहीं बढ़ाया जाएगा जब तक कि ऐसी मंजूरी प्राप्त न हो जाए, जब तक कि उन्हीं तथ्यों पर अभियोजन के लिए मंजूरी पहले ही प्राप्त न कर ली गई हो जिन पर परिवर्तित या जोड़े गए आरोप आधारित हैं।

7. उपरोक्त धारा के अवलोकन से इस बात में कोई संदेह नहीं रह जाता कि स्पष्ट रूप से, विद्वान न्यायालय को यह शक्ति प्राप्त है कि वह मुकदमे के दौरान किसी आरोप को बदलने या जोड़ने के लिए राय बना सकता है, बशर्ते कि इससे अभियुक्त को उसके बचाव में कोई नुकसान न हो या ऐसे परिवर्तन या जोड़ने के बाद मुकदमा बिना किसी बाधा के आगे बढ़ेगा, जैसे कि यह मूल आरोप के आधार पर आगे बढ़ता।

8. उक्त प्रावधान मुकदमे के दौरान आरोप तय करने के लिए एक संतुलित दृष्टिकोण प्रदान करता है। इस तरह की शक्ति का प्रयोग ट्रायल जज द्वारा केवल अपने स्वयं के अनुरोध पर किया जाना चाहिए ताकि वह पूरी तरह से तटस्थ हो और किसी पक्षपाती पक्ष के अनुरोध पर ऐसा न लगे। धारा 216 यह सुनिश्चित करती है कि न्यायालय के पास नए साक्ष्य या कानूनी विचारों के आधार पर आरोपों को समायोजित करने की लचीलापन है, लेकिन साथ ही अभियुक्त के निष्पक्ष सुनवाई के अधिकारों को संभावित पूर्वाग्रह से सुरक्षित रखा जाता है। प्रक्रियागत सुरक्षा उपायों को बरकरार रखा जाना चाहिए ताकि किसी आरोपी/अंडरट्रायल के अधिकारों को खतरे में न डाला जा सके।

9. वर्तमान मामले में, अतिरिक्त आरोप जोड़े जाने से न केवल मुकदमे की दिशा बदल जाएगी, बल्कि इससे अभियुक्तों को दी जाने वाली सजा के संबंध में उनके अधिकार भी गंभीर रूप से प्रभावित होंगे, क्योंकि धारा 468 के तहत आजीवन कारावास की सजा का प्रावधान है, जबकि आईपीसी की धारा 420 के तहत 7 वर्ष की सजा का प्रावधान है। इस संदर्भ में, पी. कार्तिकलक्ष्मी बनाम श्री गणेश एवं अन्य आपराधिक अपील संख्या 1709/2014, (2017) 3 एससीसी 347 में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय का संदर्भ लिया जा सकता है। इसका प्रासंगिक भाग नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया है:-

> "7. इस संदर्भ में हमें धारा 221 और 222 सीआरपीसी के बारे में बताया गया। इस मामले में शामिल तथ्यों के मद्देनजर, हम केवल धारा 216 सीआरपीसी से संबंधित हैं। इसलिए, हम मामले में अन्य प्रावधानों के निहितार्थों की जांच करने का प्रस्ताव नहीं रखते हैं। हम धारा 216 के आह्वान तक ही खुद को सीमित रखना चाहते हैं और उसी पर विचार करना चाहते हैं। हमारे इस निष्कर्ष के मद्देनजर कि धारा 216 सीआरपीसी के आह्वान की शक्ति केवल न्यायालय के पास ही सीमित है, जो निर्णय सुनाए जाने से पहले किसी भी समय किसी भी आरोप को बदलने या जोड़ने के उद्देश्य से सक्षम प्रावधान है, हम यह स्पष्ट करते हैं कि किसी भी पक्ष, न तो वास्तविक शिकायतकर्ता और न ही अभियुक्त या उस मामले के लिए अभियोजन पक्ष के पास आरोप में किसी भी तरह के जोड़ या परिवर्तन की मांग करने का कोई निहित अधिकार नहीं है, क्योंकि यह धारा 216 सीआरपीसी के तहत प्रदान नहीं किया गया है। यदि पक्षकारों द्वारा ऐसा रास्ता अपनाने की अनुमति दी जाती है, तो आपराधिक न्यायालय के लिए अपनी कार्यवाही समाप्त करना लगभग असंभव हो जाएगा और त्वरित सुनवाई की अवधारणा खतरे में पड़ जाएगी।
>
> 8. ऐसी परिस्थितियों में, जब अपीलकर्ता द्वारा स्वयं ट्रायल कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत किया गया आवेदन विचारणीय नहीं था, तो ट्रायल कोर्ट के लिए धारा 216 सीआरपीसी के तहत आदेश पारित करना आवश्यक नहीं था। इसलिए, धारा 397 सीआरपीसी के तहत उक्त आदेश को संशोधित करने का कोई सवाल ही नहीं था। अपीलकर्ता के कहने पर शुरू की गई पूरी कार्यवाही विचारणीय नहीं थी। चूंकि

कानूनी मुद्दे को आवश्यक रूप से ठीक करना था, इसलिए हम धारा 216 सीआरपीसी के तहत उपलब्ध कानून को स्पष्ट करने के लिए बाध्य हैं। उस सीमा तक, कानूनी स्थिति को स्पष्ट करने के बाद, हम यह स्पष्ट करते हैं कि अपीलकर्ता के कहने पर शुरू की गई पूरी कार्यवाही पूरी तरह से गलत थी और कानून में दोषपूर्ण थी और ट्रायल कोर्ट द्वारा इस पर विचार नहीं किया जाना चाहिए था। जैसा कि प्रतिवादी 1 के विद्वान वरिष्ठ वकील ने सही कहा है, अपीलकर्ता द्वारा अपनाए गए इस तरह के कदम और निचली अदालत द्वारा स्वीकार किए जाने से अनावश्यक रूप से कार्यवाही को लंबा खींचने की गुंजाइश पैदा हो गई है, जिसकी निचली अदालत को अनुमति नहीं देनी चाहिए थी।

10. उपरोक्त के मद्देनजर और इस आदेश के पिछले भाग में दर्ज की गई मेरी चर्चा के परिणामस्वरूप, आक्षेपित आदेश कायम नहीं रखा जा सकता है और इसे अनिवार्य रूप से रद्द किया जाना चाहिए। ऐसा आदेश दिया जाता है।

11. याचिका का निपटारा किया जाता है और चूंकि अतिरिक्त आरोप खारिज कर दिए गए हैं, इसलिए मुकदमा आरोपी के खिलाफ लगाए गए मूल आरोपों के आधार पर कानून के अनुसार आगे बढ़ेगा।

12. लंबित आवेदन, यदि कोई हो, का भी निपटारा किया जाता है।

(अरुण मोंगा),जे

यह अनुवाद आर्टिफ़िश्यल इंटेलिजेंस टूल "सुवास" के जरिये अनुवादक की सहायता से किया गया है ।
अस्वीकरण - यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा मे अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी आधिकारिक एवं व्यवहारिक उद्देश्यों के लिए उक्त निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा एवं निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।